letter/representation has been received in recent times from the Mazdoor Kishan Shakti Sangathan, Rajasthan urging for C.B.I. probe into rural development scam of the state.

(c) The amount released to the State of Rajasthan under major rural development/employment schemes viz. Jawahar Rozgar Yojana (JRY), employment Assurance Scheme (EAS) Integrated Rural Development Programme (IRDP), Indira Awaas Yojana (IAY), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), Drought Prone Area Programme (DPAP) & Desert Development Programme (DDP) during last three years is given below:—

Amount released (Rs. in lakhs)

Programme	1994-95	1995-96	1996-97
J.R.Y.	14680.78	15060.74	7231.81
E.A.S.	9900 00	14030 00	10390.00
I.R.D.P.	2017.03	1969.62	2205.74*
I.A.Y.	1506 86	5167.49	4032 70
A.R.W.S.P.	8231 00	6908 00	8456 00
DPAP	426 50	643.77	152 00
D.D.P.	6450 00	5358 00	1639.91

*Includes G.K.Y.

(d) Various types of monitoring mechanism used to review the progress of Rural Development Employment Programmes are, periodical progress reports, review meetings by senior officers, concurrent Evaluation Studies, field visits by senior officers etc. Short comings, if any, observed are brought to the notice of State Governments.

स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता

2442. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने के लिए स्वरोजगार प्रारम्भ करने के इच्छुक नौजवानों को वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995–96 और 1996–97 में स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए देश के ग्रामीण अंचलों में वित्तीय आवश्यकता की राशि के संबंध में क्या अनुमान किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि की उपलब्धता हेतु कोई व्यवस्था कायम करने पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडू) : (क) से (घ) स्वरोजगार प्रारम्भ करने के इच्छुक युवकों की वित्तीय आवश्यकता के अनुमान से संबंधित आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस मंत्रालय के पास गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में वर्ष 1992–93 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों

के प्रतिशत का अनुमान है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध, कराया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार ऋण जुटाने और प्रति परिवार निवेश के बारे में लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1995–96 और 1996–97 के लिए प्रति परिवार निवेश लक्ष्य क्रमशः 14,000 रुपये और 15,000 रुपए था। इसके अलावा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वे प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें ।

गुजरात में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कपार्ट) योजना

2443. **श्री अनंतराय देवशंकर दवे:** **क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् योजना के विस्तार तथा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में "कपार्ट" के अंतर्गत जिला-वार कौन-कौन सी योजनाएं सफलता-पूर्वक कार्यान्वित की गई हैं तथा कौन-कौन सी योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई;

(घ) क्या "कपार्ट" योजनाओं का प्रसार सही ढंग से नहीं किया गया है; और

(ङ) राज्य के आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु) : (क) से (ग) 1994 में अहमदाबाद में कपार्ट की क्षेत्रीय समिति की स्थापना से कपार्ट गुजरात में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम हुआ है। इसके फलस्वरूप कपार्ट द्वारा गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि हुई है । विगत 3वर्षों के दौरान गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों की 289 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है । इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 1085.44 लाख रुपए हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं [**देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 65**] कपार्ट ने सूचित किया है कि स्वीकृत परियोजनाओं को कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया है/किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) कपार्ट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रचारित और लोकप्रिय बनाने के विचार से अहमदाबाद स्थित इसकी क्षेत्रीय समितियां आवश्यकता आधारित परियोजना प्रस्तावों का पता लगाने और बनाने में स्वैच्छिक संगठनों तथा जनजातीय क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन में गुजरात राज्य के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाता है । इसके अतिरिक्त, कपार्ट की गृह पत्रिका में उपलब्धियां प्रकाशित की जाती हैं। इन उपायों के अलावा कपार्ट इस प्रयोजनार्थ आकाशवाणी दूरदर्शन और क्षेत्रीय समाचार पत्रों जैसे मास मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है ;

Implementation of land reforms

2444. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the land reforms measures are not being implemented effectively in several States and particularly in Orissa;

(b) if so, the reasons for the tardy progress of the land reforms measures;